THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) The gap between the rich and the poor in the country measured in terms of ratio of per capita consumption of richest 30 per cent and poorest 30 per cent of the population, according to the National Sample Survey (NSS) data on Household Consumer Expenditure, (of two latest periods), is observed to decline from 3.55 in 1987-88 to 3.43 in 1993-94. Separate information for Calcutta is not available.

(b) No, Sir.

(c) The estimates of income are not available. The per captita consumption expenditure of the people living below the poverty line (35.97% of the total population), according to NSS data of 50th round is estimated as Rs. 172 per month in 1993-94.

(d) There is a three-pronged attack on poverty, i.e. (i) acceleration of economic growth, (ii) human and social development through literacy, education, health, nutrition, meeting the minimum needs, elevation of social and economic status of the weaker sections of the society, etc., and (iii) direct attack on poverty through employment and income generating programmes and asset-building for the poor. The main among these programmes are the Integrated Rural Development Programme, Jawahar Rozgar Yojana, Nehru Rozgar Yojana and Prime Minister's Rozgar Yojana for the Educated Unemployed Youth. A Basic Minimum Services Programme has also been launched last year.

गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों के आंकड़े

2010. **श्री राम जेठमलानी:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 दिसम्बर, 1996 के "टाइम्स ऑफ इण्डिया" में "न्यू मैथडोलॉजी डबल्स पावर्टी फिगर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार ने उन व्यक्तियों को, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 228 रुपये प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में 264 रुपये प्रति-माह प्राप्त कर रहे हैं; वर्ष 1992-93 के मूल्यों के आधार पर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्ति मानने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का मापदंड क्या है; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होने का अनुमान है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्र (श्री योगेन्द्र भगतराम अलघ): (क) जी, हां.

(ख) और (ग) 1973-74 की कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 49.09 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 56.64 रुपये के मासिक प्रतिव्यक्ति उपभोग व्यय के रुप में अभिव्यक्त कृतिक बल गरीबी रेखा को 1993-94 की कीमतों के आधार पर क्रमशः 229.14 रुपये और 264.38 रुपये तक अद्यतन किया गया है यद्यपि हाल ही में अपनाई गई सरकारी पद्धति, जो विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट पर आधारित है, का पालन करते हुए गरीबी रेखाओं को राज्य-स्तर पर संगठित किया जाता है.

(घ) योजना आयोग उपभोक्ता व्यय पर पंचवार्षिक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के आंकड़ों का उपयोग करते हुए गरीबी के मामलों का अनुमान लगाता है. गरीबी के नवीनतम अनुमान 1993-94 वर्ष के लिए उपलब्ध है जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के 50वें दौर पर आधारित है हाल ही में अपनाई गई सरकारी पद्धति, जो गरीबों के अनुपात और संख्या के अनुमान पर विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट पर आधारित है, का पालन करते हुए 1934-94 में गरीबी के 35.97 प्रतिशत होने का अनुमान है.

Release of MPLADS funds

2011. SHRIMATI VEENA VERMA: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether funds under Members of Parliament Local Area Development Scheme for 1996-97 have been released in respect of all the MPs;